

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 3421 / 2024

डॉ. जुल्फिकार अहमद काजी

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3/शिका.) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.11.2024

आदेश की दिनांक : 24.12.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 22.08.2024 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को बहाल करते हुये पदस्थापित कर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर हाल निलंबित मुख्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 22.08.2024 के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 170/2024 अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में प्रथम दृष्ट्या लिप्त पाये जाने पर दिनांक 11.08.2024 को गिरफ्तार किया गया और वह 48 घण्टों से अधिक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रहा, जिसके कारण अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम के नियम 13(2) के अंतर्गत अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.08.2024 के द्वारा निलंबित किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी को निलंबित हुये 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। न तो विभाग द्वारा कोई आरोप पत्र दिया गया है और न ही सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र/चालान प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार लम्बे समय तक निलंबित रखा जाना विधि विरुद्ध है। माननीय अधिकरण एवं माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निलंबन के संबंध में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि विभागीय जांच के संबंध में निलंबन के पश्चात् 90 दिवस में आरोप पत्र नहीं दिया जाता अथवा फौजदारी/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रकरणों में 90 दिवस में सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र/चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो निलंबन आदेश को बनाये रखना अनुचित व अवैध है। ऐसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अजय कुमार चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में सिद्धांत प्रतिपादित किया है और इस प्रकार लम्बे समय तक कार्मिक को निलंबित रखा जाना उचित नहीं माना है। अतः अपीलार्थी का प्रकरण भी उक्त मामले के समान है और 90 दिवस से अधिक समय तक अपीलार्थी को निलंबित रखा जाना उक्त विधि के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 22.08.2024 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को बहाल करते हुये पदस्थापित कर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध एसीबी द्वारा अपराध संख्या 170/2024 अंतर्गत धारा 7 दिनांक 11.08.2024 को अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया और अपीलार्थी 48 घण्टे से अधिक पुलिस/न्यायिक हिरासत में रहा, जिसके कारण अपीलार्थी को नियमानुसार आलोच्य आदेश दिनांक 22.08.2024 के द्वारा निलंबित किया गया। एसीबी द्वारा जांच प्रक्रियाधीन और पूर्ण होने पर आरोप पत्र/चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा और विभाग द्वारा जांच प्रक्रियाधीन है। विभागीय जांच में दोषी पाये जाने पर अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर हाल निलंबित मुख्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 22.08.2024 के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 170/2024 अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में प्रथम दृष्ट्या लिप्त पाये जाने पर दिनांक 11.08.2024 को गिरफ्तार किया गया और वह 48 घण्टों से अधिक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रहा, जिसके कारण अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम के नियम 13(2) के अंतर्गत अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.08.2024 के द्वारा निलंबित किया गया। जहां तक अपीलार्थी को निलंबित हुये 90 दिवस से अधिक अवधि हो जाने के पश्चात् विभाग द्वारा न तो आरोप पत्र अपीलार्थी को दिये जाने और न ही सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाने पर अपीलार्थी को लम्बे समय तक निलंबित रखे जाने का प्रश्न है, आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक

22.08.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दिनांक 11.08.2024 से निलंबित किया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी को उक्त आदेश के द्वारा निलंबित हुये 90 दिवस से भी अधिक का समय बीत चुका है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में भी यह स्पष्ट अंकित है कि अपीलार्थी के विरुद्ध विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है और जांच पूर्ण होने उपरांत दोषी पाये जाने पर उसे आरोप पत्र दे दिया जायेगा। परंतु अपीलार्थी को आलोच्य निलंबन आदेश जारी होने के बाद 90 दिवस से भी अधिक का समय बीत चुका है, परंतु अपीलार्थी के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (2015) 7 एससीसी 291 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 जिसमें निलंबन के तीन माह पूर्ण होने पर आरोप पत्र नहीं दिये जाने के संबंध में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :-

"We, therefore, direct that the currency of a Suspension Order should not extend beyond three months if within this period the Memorandum of Charges/Chargesheet is not served on the delinquent officer/employee; if the Memorandum of Charges/Chargesheet is served a reasoned order must be passed for the extension of the suspension. As in the case in hand, the Government is free to transfer the concerned person to any Department in any of its offices within or outside the State so as to sever any local or personal contact that he may have and which he may misuse for obstructing the investigation against him. The Government may also prohibit him from contacting any person, or handling records and documents till the stage of his having to prepare his defence. We think this will adequately safeguard the universally recognized principle of human dignity and the right to a speedy trial and shall also preserve the interest of the Government in the prosecution. We recognize that previous Constitution Benches have been reluctant to quash proceedings on the grounds of delay, and to set time limits to their duration. However, the imposition of a limit on the period of suspension has not been discussed in prior case law, and would not be contrary to the interests of justice. Furthermore, the direction of the Central Vigilance Commission that pending a criminal investigation departmental proceedings are to be held in abeyance stands superseded in view of the stand adopted by us.

So far as the facts of the present case are concerned, the Appellant has now been served with a Chargesheet, and, therefore, these directions may not be relevant to him any longer. However, if the Appellant is so advised he may challenge his continued suspension in any manner known to law, and this action of the Respondents will be subject to judicial review."

इस प्रकार उक्त न्यायिक विनिश्चय के अनुसार अपीलार्थी को लम्बे समय तक निलंबित रखा जाना उक्त विधि के विरुद्ध है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 22.08.2024 को उक्त न्यायिक विनिश्चय को दृष्टिगत रखते हुये अपास्त किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य